

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 26, बुधवार, शाके 1947- अप्रेल 16, 2025 Chaitra 26, Wednesday, Saka 1947- April 16, 2025	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 15, 2025

संख्या प.2(12)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 11)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2025 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए; तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 और कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“24. न्यास के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, न्यास के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।”।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (घ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (गग) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(गग) न्यास की किसी सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने, और धारा 24 के अधीन किसी अन्य कारण के लिए;”।

4. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 77-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 77 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 11 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“77-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे न्यास द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, न्यास द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व न्यास द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के

अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 3

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

5. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 8 का संशोधन.- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

6. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

7. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

8. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 96-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96 के पश्चात् और विद्यमान धारा 97 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"96-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"

अध्याय 4

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 8 का संशोधन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

10. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

11. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 91 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 91 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

12. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 92-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 92 के पश्चात् और विद्यमान धारा 93 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"92-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 5

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में संशोधन

13. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 8 का संशोधन.- अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि, जो" के

पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान राज्य” से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति “जिला न्यायाधीश या” हटायी जायेगी।

14. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"

15. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 91 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 91 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"

16. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 92-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 92 के पश्चात् और विद्यमान धारा 93 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"92-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में किसी अन्तर्विष्ट प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

अध्याय 6

उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 में संशोधन

17. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 8 का संशोधन.- उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 28), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि, जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

18. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

19. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"

20. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 की धारा 96-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96 के पश्चात् और विद्यमान धारा 97 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"96-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"

अध्याय 7

कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 में संशोधन

21. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 8 का संशोधन.- कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 31), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, विधि, जो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य" से पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश या" हटायी जायेगी।

22. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए एक पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।"।

23. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (1-क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1-क) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।"।

24. 2023 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 96-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96 के पश्चात् और विद्यमान धारा 97 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"96-क. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधियां या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तदधीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।"।

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 15, 2025

No. F. 2(12)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vidhiyan (Sansodhan) Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 11):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) ACT, 2025

(Act No. 11 of 2025)

(Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2025)

An

Act

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Ajmer Development Authority Act, 2013; and to amend the Udaipur Development Authority Act, 2023 and the Kota Development Authority Act, 2023.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing section 24 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“24. Power to create separate common service for the Trust.- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Trust, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..”.

3. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- In sub-section (1) of section 74 of the principal Act, after the existing clause (c) and before the existing clause (d), the following new clause (cc) shall be inserted, namely:-

“(cc) for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Trust for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 24;”.

4. Insertion of section 77-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 77 and before the existing CHAPTER-XI of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“**77-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Trust, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Trust that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Trust prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.”.

CHAPTER-III

AMENDMENT IN THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

5. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression “below the rank of” and before the existing expression “Joint Legal Remembrancer”, the expression “District Judge, or” shall be deleted.

6. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**9. Power to create separate common service for the Authority.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate

common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc. .”.

7. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 95 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

“(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.”.

8. Insertion of section 96-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 96 and before the existing section 97 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“96-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.”.

CHAPTER-IV

AMENDMENT IN THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009

9. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing

expression “below the rank of” and before the existing expression “a Joint Legal Remembrancer”, the expression “a District Judge, or” shall be deleted.

10. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“9. Power to create separate common service for the Authority.- (1)

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..”.

11. Amendment of section 91, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 91 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

“(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.”.

12. Insertion of section 92-A, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- After the existing section 92 and before the existing section 93 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“92-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.- (1)

Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.”.

CHAPTER-V

AMENDMENT IN THE AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013

13. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression “below the rank of” and before the existing expression “a Joint Legal Remembrancer”, the expression “a District Judge or” shall be deleted.

14. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“9. Power to create separate common service for the Authority.- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..”.

15. Amendment of section 91 of Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 91 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

“(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.”.

16. Insertion of section 92-A, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 92 and before the existing section 93 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“92-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is

inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.”

CHAPTER-VI

AMENDMENT IN THE UDAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2023

17. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 28 of 2023.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Udaipur Development Authority Act, 2023 (Act No. 28 of 2023), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression “below the rank of” and before the existing expression “a Joint Legal Remembrancer”, the expression “a District Judge or” shall be deleted.

18. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 28 of 2023.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**9. Power to create separate common service for the Authority.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..”

19. Amendment of section 95 of Rajasthan Act No. 28 of 2023.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 95 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

“(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of the services of the Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.”

20. Insertion of section 96-A, Rajasthan Act No. 28 of 2023.- After the existing section 96 and before the existing section 97 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“**96-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for

the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.”.

CHAPTER-VII

AMENDMENT IN THE KOTA DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2023

21. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- For the existing clause (iv) of sub-section (2) of section 8 of the Kota Development Authority Act, 2023 (Act No. 31 of 2023), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression “below the rank of” and before the existing expression “a Joint Legal Remembrancer”, the expression “a District Judge or” shall be deleted.

22. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“9. Power to create separate common service for the Authority.- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create a separate common service for the Authority, ensuring uniformity in administration and governance.

(2) The State Government shall have the power to determine the nomenclature, structure, and cadre strength of the service created under sub-section (1), and may, from time to time, modify or revise the same as it considers appropriate.

(3) The State Government may, in respect of the service created under this section,-

(a) sanction the creation of posts, their classification, control, and the terms and conditions of service, including recruitment, promotion, and retirement; and

(b) frame and enforce common service rules, applicable to the services created under this section, prescribing the qualifications, methods of appointment, and duties of persons to be appointed to the services, etc..”.

23. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 95 of the principal Act, the following new sub-section (1-A) shall be inserted, namely:-

“(1-A) The State Government may make rules for prescribing strength, salary, the conditions of service and emoluments, recruitment, granting leave, censuring, reducing, suspending or dismissing an employee of any of service of the

Authority for misconduct and dispensing with their services for any other reason under section 9.”.

24. Insertion of section 96-A, Rajasthan Act No. 31 of 2023.- After the existing section 96 and before the existing section 97 of the principal Act the following new section shall be inserted therein, namely:-

“96-A. Supremacy of rules and Repeal of Existing Regulations.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or regulation for the time being in force, the rules made under this Act shall have overriding effect and shall prevail over any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority, insofar as such regulations, bylaws, or notifications are inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Upon the commencement of this Act and the enforcement of rules thereunder, any regulation, bylaw, or notification issued by the that is inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall stand repealed to the extent of such inconsistency.

(3) Any action taken or decision made under any regulation, bylaw, or notification issued by the Authority prior to the commencement of this Act shall remain valid unless expressly invalidated by the rules framed under this Act.”.

ब्रजेन्द्र जैन,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।